

अपील संख्या:—जीसीएमएस नं. 2021/271 न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

1. पवन मोदी आयु 58 वर्ष पुत्र श्री चिरंजीलाल मोदी जाति महाजन मोदी निवासीगण अजीतगढ़ तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मण्डावा जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थिति:—

1. श्री दलीपसिंह करनावत, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक: 23.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट की पट्टेशुदा मिल्कियत व कब्जे की दो पट्टों शुदा आबादी की भूमि 825 वर्गगज वाके ग्राम अजीतगढ़ उप तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की बाबत पटवारी हल्का अजीतगढ़ ने एक गलत रिपोर्ट नायब तहसीलदार मण्डावा को दिनांक 12.01.2021 को इस आशय की पेश की कि ग्राम अजीतगढ़ स्थित भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 4.25 हैक्टर गैर मु. बणी में से 700 वर्गमीटर भूमि पर पवन मोदी पुत्र चिरंजीलाल मोदी जाति महाजन निवासी ने पत्थर लगाकर तारबंदी कर अतिक्रमण किया है, पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण नायब तहसीलदार ने दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट द्वारा जवाब नोटिस मय प्रतिलिपि पट्टा दिनांक 22.08.1971 व प्रतिलिपि पट्टा दिनांक 30.07.1977 ग्राम पंचायत अजीतगढ़ का जो अपीलान्ट के पिता श्री चिरंजीलाल मोदी वल्द श्री शिवलाल मोदी को जारी किया गया था, पेश किया उसके उपरान्त भी नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को बिना सुने ही गलत व गैरकानूनी रूप से निर्णय दिनांक 20.04.2021 पारित कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा भी प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर विधि अनुसार कोई गौर किये बिना ही दिनांक 16.08.2021 को गैरकानूनी निर्णय पारित कर दिया गया। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की दोनों पट्टेशुदा भूमि 825 वर्गगज वाके ग्राम अजीतगढ़ आबादी की भूमि है व उसके आस-पास आबादी बसी हुई है, अपीलान्ट्स के पिता के पास रिहायश की भूमि पर्याप्त न होने से उनके प्रार्थना पत्र पर वादग्रस्त भूमि का पट्टा आबादी हेतु अपीलान्ट के

P.T.O.

पिता चिरंजीलाल मोदी को दिनांक 22.08.1971 व 30.07.1977 को ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा जारी किया गया है, अपीलान्त के पिता चिरंजीलाल उक्त पट्टेशुदा भूमि वादग्रस्त 825 वर्गगज भूमि के मालिक व काबिज थे एवं अपीलान्ट्स के पिता चिरंजीलाल का देहान्त हो जाने के पश्चात् उसके वारिसान अपीलान्ट उक्त 825 वर्गगज भूमि के मालिक व काबिज हो गये तथा अपीलान्ट की मिल्कियत व कब्जे की उक्त 825 वर्गगज भूमि वादग्रस्त आबादी की भूमि है, आबादी भूमि की बाबत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही कानूनन नहीं की जा सकती है तथा आबादी की भूमि बाबत किसी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नायब तहसीलदार मण्डावा को कानूनन प्रदत्त नहीं है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त पट्टे से सम्बन्धित खसरा नम्बर 182 रकबा 4.25 हैक्टर, गत खसरा नम्बर 148 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा था एवं ग्राम पंचायत अजीतगढ़ ने अपनी बैठक दिनांक 12.10.1975 व 31.07.1976 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ग्राम अजीतगढ़ में आबादी विस्तार के लिए भूमि आवंटन करने की प्रार्थना तहसीलदार झुन्डुनू से की थी उन्होंने इस प्रयोजन हेतु ग्राम अजीतगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 148, 149, तथा खसरा नम्बर 153 में से कुल 15 बीघा भूमि आवंटन करने के लिए तहसीलदार से निवेदन किया तथा सरपंच ग्राम पंचायत अजीतगढ़ ने अपने आवेदन पत्र में यह भी निवेदन किया कि प्रस्तावित भूमि आबादी के पास है, पहले यहाँ ही ग्राम पंचायत द्वारा नागरिकों को पट्टे भी दिये गये थे, तहसीलदार झुन्डुनू ने जांच कर पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर गत खसरा नम्बर 148, 149, व 153 में क्रमशः 3 बीघा 14 बिस्वा, 1 बीघा 6 बिस्वा व 10 बीघा कुल किता 15 बीघा भूमि चारागाह से बारानी सोयम में रूपान्तरित कर ग्राम पंचायत द्वारा कथित प्रयोजन की पूर्ति हेतु आवंटित करने की सिफारिश जिला कलक्टर झुन्डुनू से दिनांक 19.01.1977 को की गई तथा जिला कलक्टर झुन्डुनू ने उक्त वर्णित 15 बीघा भूमि की किस्म चारागाह से बारानी सोयम में रूपान्तरित करने बाबत राज्य सरकार को दिनांक 02.02.1977 को जरिये पत्र सिफारिश की व इस सम्बन्ध में उप शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग से निवेदन किया एवं राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प. 2(53)राज/3/77 दिनांक 08.04.1977 के जरिये प्रस्तावित उपरोक्त भूमि को चारागाह से खारिज कर बारानी सोयम में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जिस पर जिला कलक्टर झुन्डुनू ने दिनांक 25.04.1977 को उक्त 15 बीघा भूमि को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार बारानी सोयम में रूपान्तरित कर दी गई एवं आबादी विस्तार के लिए आबादी में घोषित कर दी तथा ग्राम पंचायत अजीतगढ़ को आबादी विस्तार के लिये आवंटन कर दी गई। इस प्रकार जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 02.02.1977 व 25.04.1977 व राज्य सरकार के उक्त आदेश दिनांक 08.04.1977 के पारित होने से यह एकदम स्पष्ट हो गया कि अपीलान्ट के पिता को ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा दिनांक 22.08.1971 व 30.07.1977 को जारी किया गया पट्टा एक वैध दस्तावेज है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अपीलान्ट का उक्त पट्टा व वादग्रस्त भूमि पर कब्जा जिला कलक्टर झुन्डुनू व राज्य सरकार के उक्त वर्णित आदेश के अनुसार व प्रकरण की तमाम परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय मातहत द्वारा नियमित किये जाने योग्य है किन्तु इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई गौर न करने में अहम कानूनी गलती की है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्डुनू द्वारा पारित अपीलान्तीन आदेश दिनांक 16.08.2021 एवं नायब

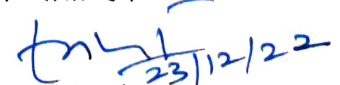
(3)

तहसीलदार मण्डावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2021 को निरस्त फरमाया जावे व अपीलान्त को उनकी मिल्कियत व कब्जे की उक्त पट्टेशुदा भूमि से बेदखल न किया जावे और यदि अपीलान्त को बेदखल कर दिया जाता है तो उनके वादग्रस्त भूमि पर कब्जा वापिस दिलवाने की कृपा करें और अपीलान्त का यह भी वैकल्पिक निवेदन है कि उनके पिता के हक में जारी किया गया पट्टा दिनांक 22.08.1971 व 30.07.1977 ग्राम पंचायत अजीतगढ़ को नियमित करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को फरमाया जावे एवं वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्त के कब्जे का नियमन करने की कृपा करें व प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

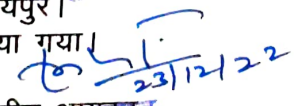
रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्त की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि जिला कलक्टर झुन्झुनू के आदेश दिनांक 25.04.1977 द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन से पूर्व ही दिनांक 22.08.1971 को अपीलान्त के पिता चिरंजीलाल मोदी को उक्त वादग्रस्त भूमि में से 675 वर्गगज भूमि के पट्टे जारी किये गये हैं जो विधि सम्मत नहीं है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज का पट्टा आवंटन दिनांक 25.04.1977 के पश्चात् अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल को दिनांक 30.07.1977 को जारी किया गया जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण 150 वर्गगज के पट्टे की हद तक रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 को अपीलार्थी को ग्राम पंचायत अजीतगढ़ द्वारा जारी 150 वर्गगज के पट्टे की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार मण्डावा जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर 150 वर्गगज भूमि के पट्टे के सम्बन्ध में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। शेष 675 वर्गगज भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है।


(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर।